



Selectors need to have a vision, else it won't work out: Dilip

The Mumbai-based Vengsarkar spoke to this Columnist for over an hour.

The Chewy Chapter

YOGA: Manage Diabetes with These Asanas

Yoga can do more than just relax your body & mind.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से आए चीतों को मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर लगभग 70 वर्षों बाद देश में फिर से चीता बसाने की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। नामीबिया से पहले चरण में आठ चीते विशेष विमान से मध्यप्रदेश लाए गए, जिनमें पांच मादा और तीन नर हैं। केन्द्र सरकार की देश में चीतों को फिर से बड़े पैमाने पर बसाने की योजना के तहत सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल इन चीतों को वन्यजीव विशेषज्ञों की देखरेख में रखा गया है, ये लोग चीतों की प्रत्येक गतिविधि पर बारीकी से नजर रखेंगे। लगभग पांच घंटों की मध्यप्रदेश यात्रा के दौरान मोदी ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के लिए बनाए गए विशेष बाड़े के पास बनी मचान पर खड़े होकर दो विशेष पिंजरे खोले, जिसके साथ ही चीते बाहर निकलकर बाड़े में विचरण करने लगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में मोदी ने चीतों को विचरण करते हुए न सिर्फ काफी नजदीक से देखा, बल्कि इन ऐतिहासिक क्षणों को अपने कैमरे में कैद भी किया। मोदी ने राष्ट्रीय उद्यान में ही चीता मित्रों से संवाद किया। राष्ट्रीय उद्यान के कारण विस्थापित ग्रामीणों में से कुछ का चयन कर उन्हें चीता मित्र बनाया गया है, जो चीतों की सुरक्षा का कार्य देखेंगे। इसके अलावा उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्र. मंत्री मोदी ने चीतों को पार्क में छोड़ने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए चीतों की सुरक्षा का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि, देश में 70 सालों के बाद चीते बसाने का कार्य हो रहा है और देश के साथ ही मध्यप्रदेश के लोगों ने हमेशा उनका भरोसा कायम रखा है। इसलिए सब लोग चीतों की सुरक्षा का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि "विदेश से आए चीतों को अभी अपना घर बनाना है। इसलिए लोगों को चीतों को देखने के लिए धैर्य रखना होगा। अभी ये चीते क्षेत्र से अनजान हैं। इसलिए उन्हें कुछ महीनों का समय देना होगा।"

ज्ञानवापी मस्जिद

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। मुस्लिम समुदाय ने ज्ञानवापी मस्जिद पर दिए गए वाराणसी जिला जज के

■ मुस्लिम संगठन अडिग हैं कि, ज्ञानवापी मस्जिद में हिन्दुओं को पूजा नहीं करने दी जाएगी और इसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि, इलाहाबाद जिला जज का फैसला 1991 के पूजा स्थल कानून का उल्लंघन है।

12 सितम्बर के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है, वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी में मस्जिद में हिंदुओं को प्रार्थना पूजा का अधिकार दिया है। यही नहीं मुस्लिम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीतीश-सोनिया मुलाकात

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में

■ बिहार के मु.मंत्री नीतीश कुमार ने आगामी 25 नवम्बर को या अगले सप्ताह में कभी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात का समय मांगा है, वे उन्हें केजरीवाल, के.सी.आर. और ममता बनर्जी से मतभेद खत्म करने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे।

विपक्ष को एकजुट करने के लिए भाजपा का साथ छोड़ दिया था, ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अपनी लगातार जीत से चिंतित है यूक्रेन

भय है कि, रूस की लगातार हो रही हार व रूसी सैनिकों की युद्ध में भारी संख्या में हुई मृत्यु से कहीं पुतिन का सब्र न टूट जाये तथा वे युद्ध को और खतरनाक स्तर पर न ले जायें

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। सात माह हो चुके हैं, क्या रूस-यूक्रेन विवाद "तीसरे विश्व युद्ध" के कगार पर है? वैस्टर्न मीडिया की ग्राउण्ड रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस युद्ध में सबसे बड़ी क्षति का अनुभव कर रहा है क्योंकि यूक्रेन की फौजों ने हारी हुई जमीन का अधिकांश हिस्सा पुनः जीत लिया है जिससे रूस की फौज के मनोबल पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। कई अज्ञात बीमारियों से पीड़ित राष्ट्रपति पुतिन का धैर्य जवाब दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जैलेन्स्की ने रूस की सेना के विरुद्ध बड़ी दृढ़ता से जवाबी प्रहार किया और यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली सुरक्षा गारंटी ने पुतिन को और क्रुद्ध कर दिया है।

मीडिया की खबरें संकेत देती हैं कि रूस की सैन्य विफलता के कारण राष्ट्रपति पुतिन को उस नए विपक्ष से चुनौती मिल सकती है जो यूक्रेन पर रूस

■ इस आशंका को भुनाते हुए यूक्रेन ने अमेरिका व अन्य नाटो राष्ट्रों से और अधिक आधुनिक हथियारों की मांग की है, जिसकी पूर्ति के लिये अमेरिका व यूरोपीय देश लगभग तैयार हैं।

■ रूस ने और अधिक हथियार देने के खिलाफ नाटो देशों को चेतावनी व धमकी भी दी है।

की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ है। त्वरित जीत दर्ज ना कर पाने और अब जवाबी हमला होने के कारण रूस अपने कई सैनिकों और सैन्य उपकरणों हथियारों को खो चुका है। इससे रूस के लोगों में भारी गुस्सा है, जिसे पुतिन के विरोधी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं।

स्पेशिन न्यूज ऑनलाइन ए.एस. के अनुसार यूक्रेन की सेना देश के दक्षिण और उत्तर में हारी हुई जमीनों पर फिर से कब्जा जमा रही है, लेकिन मॉस्को से एक बड़ा जवाबी हमला होने की आशंकाओं को लेकर चिन्ता है जो कि

इस युद्ध के अपेक्षाकृत अधिक नृशंस चरण में आ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जैलेन्स्की और उनकी सरकार ने पश्चिमी देशों से भविष्य का समर्थन सुनिश्चित करने को लेकर नई सुरक्षा गारंटीयों के दस्तावेज तैयार किए हैं। जाहिर तौर पर इस दस्तावेज का उद्देश्य आगे होने वाले हमलों के विरुद्ध यूक्रेन की रक्षात्मक क्षमताओं की किलेबंदी करना है, लेकिन जैलेन्स्की द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में और आगे की बात कही गई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डब्ल्यू.एच.ओ. की चेतावनी

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने कोविड-19 के लिए असाध्य रोगियों के लिए उपयोग की जाने वाली रैमडेसिविर एंटीवायरल दवा के विरुद्ध कड़ी चेतावनी है।

■ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने एक शोध के आधार पर कोविड-19 के गंभीर मरीजों में रैमडेसिविर दवा का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी है और कहा है कि, यह दवा ओमर्कॉन पर भी कारगर नहीं है।

इसके इस्तेमाल को लेकर यह कठोर सिफारिश पूर्व सशर्त सिफारिशों का स्थान लेती और यह लैबोरेटरी स्टडीज से मिले उस साक्ष्य पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि यह दवा के ओमर्कॉन जैसे वर्तमान प्रसारित वैरिएन्ट्स के विरुद्ध संभवतया असर नहीं करती है। भारत में शनिवार को कोविड-19 के केंसों की संख्या कम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

निज़ाम शासन से मुक्ति दिवस या "तेलंगाना इन्टिग्रेसन डे"

अमित शाह व तेलंगाना के मु.मंत्री के.सी.आर. ने कुछ किलोमीटर की दूरी पर अलग-अलग झण्डा रोहण किया, एक ही दिन

-लक्ष्मण बैंकट कुची-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। तेलंगाना की राजधानी, यानी हैदराबाद शहर शनिवार को हॉटस्पॉट बन गया। इस विशिष्ट दिवस पर आयोजित समारोहों के माध्यम से केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव ने एक दूसरे की बराबरी की टक्कन दी।

जहाँ केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा निज़ाम के शासन से तेलंगाना की आजादी का जश्न मना रही थी, वहीं तेलंगाना सरकार इस दिवस को "तेलंगाना एकीकरण दिवस" के रूप में मना रही थी तथा इस प्रकार दो विचार धाराओं के बीच सीधा टक्कर देखने को मिला रहा था। दोनों ही राजनैतिक संगठन चुनावी जंग की तैयारी करते नजर आ रहे थे। जहाँ एक दल मुरगोडे विधान सभा सीट के लिये शीघ्र ही होने वाले उप चुनाव को ध्यान में रखे हुये था, वहीं दूसरा दल अगले (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ अमित शाह ने इस अवसर पर, 17 सितम्बर, 1948 को हैदराबाद को निज़ाम के शासन से मुक्ति मिलने के दिन को याद किया।

■ मु.मंत्री के.सी.आर. ने इस दिन को, "तेलंगाना एकीकरण दिवस" के रूप में मनाया।

■ दोनों ओर से झण्डा रोहण में धुआंधार भाषण हुए, एक दूसरे (भाजपा व टी.आर.एस.) के खिलाफ।

■ मु.मंत्री ने आरोप लगाया कि, इस अवसर का उपयोग भाजपा जनता को धर्म व साम्प्रदायिकता पर बांटने के लिए कर रही है। केवल आगामी उपचुनाव व बाद में अगले वर्ष तेलंगाना विधानसभा को देखते हुए ही भाजपा "हैदराबाद मुक्ति दिवस" का आयोजन कर रही है। अन्यथा आजादी के बाद जूनगढ़ का भी भारत में विलय हुआ, उसे भाजपा समारोह के रूप में क्यों नहीं मना रही।

■ अमित शाह ने तेलंगाना की के.सी.आर. सरकार पर व्यंग्य करते हुए कहा कि, वोट बैंक की राजनीति के कारण ही तेलंगाना सरकार हैदराबाद को निज़ाम शासन से मुक्ति मिलने की खुशी के रूप में मनाने से डरती है।

'भारत जोड़ो यात्रा से कोई समस्या नहीं'

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। सी.पी.आई. (एम) अर्थात् माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने कुछ पार्टी नेताओं द्वारा किये गये उन ट्वीट्स को खारिज कर दिया है, जिनमें इस बात

■ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा माकपा शासित केरल में प्रवेश कर गई है, जहां वह 18 दिन रहेगी हालांकि माकपा का कहना है कि, उन्हें कांग्रेस की इस यात्रा से कोई समस्या नहीं है, वे इसका विरोध नहीं करेंगे।

पर आपत्ति की गई थी कि कांग्रेस की "भारत जोड़ो यात्रा" कम्यूनिस्ट शासित केरल में 18 दिन तथा भाजपा-शासित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब निगाह इस पर टिकी है, कब सोनिया गांधी गहलोत को दिल्ली बुलाती हैं

यह माना जा रहा है कि, सोनिया गांधी, गहलोत से मु.मंत्री पद से इस्तीफा ले लेंगी और तब गहलोत से कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव का पर्चा दाखिल करवायेंगी

-रेणु मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। इस समय सभी लोगों की नज़रें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिकी हुई हैं कि वे अशोक गहलोत को मिलने के लिये कब बुलाती हैं। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि वे अशोक गहलोत को, पार्टी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरने से पहले, राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिये कह सकती हैं ताकि नये मुख्यमंत्री को नियुक्ति कर रास्ता साफ हो सके तथा पार्टी नेतृत्व इसके लिए पर्यवेक्षक भेजे तथा वह सारी कवायद हो, जो इस प्रकार की प्रक्रियाओं का हिस्सा बन चुका है।

सूत्रों ने कहा कि इस मुद्दे को गहरन जानकारी रखने वाले लोगों का मानना है कि अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष एवं तथाकथित हाईकमान बन जाने के बाद,

■ तर्क यह है कि, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद गहलोत अपना वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं, सचिन पायलट को मु.मंत्री बनने से रोकने के लिये।

■ बहरहाल 24 सितम्बर को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिये पर्चा दाखिल होंगे, तब स्थिति और स्पष्ट हो जायेगी।

■ फिलहाल दिल्ली में वरिष्ठ नेता व राजनीतिक ऑब्ज़र्वर अभी भी मानते हैं कि, गहलोत किसी न किसी तरह यह "मैनेज" करने में सफल होंगे कि, पायलट मु.मंत्री न बनें।

■ एक तर्क यह है कि, गांधी परिवार कांग्रेस का नेतृत्व अपने पास ही रखना चाहेगा, ताकि भाजपा द्वारा ई.डी. आदि केन्द्रीय एजेंसियों के जरिए पूछताछ के नाम पर लगातार उन्हें तंग करने के प्रयास को विफल किया जा सके।

सचिन पायलट के नाम के खिलाफ अपने विशेषाधिकार (वीटो) का उपयोग कर सकते हैं तथा यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे मुख्यमंत्री न बनें। दिल्ली के ज्यादातर राजनैतिक पर्यवेक्षकों तथा नेताओं का गहलोत की इस क्षमता में पूरा विश्वास है कि वे सचिन पायलट का पूरा खेल बिगाड़ते हुये, उन्हें दरकिनार कर दें।

अध्यक्ष पद की नामांकन प्रक्रिया 24 सितम्बर को शुरू होगी तथा उससे पहले ही, राजस्थान कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट हो जाने की उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस के कुछ वर्गों का विचार है कि इस समय गांधी परिवार को नेतृत्व अपने पास ही रखने की जरूरत है ताकि वह भाजपा नेतृत्व द्वारा परेशान किये जाने से बचा रहे, जैसा कि नेशनल हैरल्ट केस में ई.डी. द्वारा किया गया था।